

प्रेषक,  
डी0एस0 गब्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक/ 0 अक्टूबर, 2016

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरपालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर के पत्रांक-570/अवस्थापना/2016-17, दिनांक 03.09.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार संस्तुत कुल ₹25.82 लाख (रूपये पच्चीस लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत स्वीकृत
1.	सेलवाणी में मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य।	4.41
2.	सोननगर में सी0सी0 मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य।	4.83
3.	रामपुरा में श्री बीरेन्द्र सिंह बर्वाल एवं श्री डिमरी के मकान के समीप मार्ग एवं नाली निर्माण	3.64
4.	रोड़ से क्षेत्रपाल गांव की ओर सड़क निर्माण ।	5.00
5.	बुराली रामपुरा में सी0सी0 मार्ग निर्माण।	4.81
6.	पठियालधार पपड़ियाणा में एस0एस0बी0 के समीप मार्ग निर्माण।	3.13
योग-		25.82

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जा रही है:-

1. उक्त धनराशि कुल ₹25.82 लाख (रूपये पच्चीस लाख बयासी हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
3. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिसासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं/कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
5. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

6. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
7. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
9. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
10. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
11. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
12. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
13. धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
15. धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹20.40 लाख, अनुदान सं0-30 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-42-अन्य व्यय के नामे ₹4.65 लाख तथा अनुदान सं0-31 के लेखाशीर्षक- 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191- स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹0.77 लाख डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई डी-S.16/0.3.0.1.4.2, S.16/0.3.0.0.1.4.3 एवं S.16/0.3.1.0.1.4.4 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०एस० गर्बाल)  
सचिव।

संख्या-1788(1)/IV(2)-श०वि०-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, गढ़वाल सण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी०एस० राणा)  
उप सचिव।

